providing an amount of Rs. 1.15 crores from Consumer Welfare Fund for distributing the instruments weights and measures and scientific oils required for testing to 300 Consumer Organistions in the State. The Central Government has requested the State Government to furnish the details of the project for further processing.

Import of Coal

2088. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government propose to import coal to meet the requirement of energy sector; and

(b) if so, the details of the proposals?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) There is no proposal under consideration of the Government to import coal. Coal can be freely imported under the present import policy and the same is made by the consumers themselves considering their needs and exercising their own commercial judgement.

Safety measures in mines

2089. SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI JIBON ROY:
DR. BAPU KALDATE:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government are satisfied with the safety measures adopted in mines under BCCL; and

(b) whether Government verified the implementation of safety measures in mines?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) The coal companies including Bharat Coking Coal Limited (BCCL) are conducting mining operations as per the safety standards laid down in the Mines Act, 1952, the Coal Mines Regulations, 1957 and Rules,. Orders and Bye-laws made thereunder.

Further Government is promoting self-regulation by coal companies through internal safety audits, workers participation in safety management, tripartite/bipartite reviews at various levels, training and re-training of work persons, observance of safety weeks/safty campaigns and National Safety awards.

गेहूं की वसूली

2090. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या खाद्य मंत्री 14 अगस्त, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1467 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) सरकार ने कितनी मात्रा में और किस दर से गेहूं की खरीद की हैं और इसकी वसूली पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई हैं और सरकार के पास अब तक खाद्यान्न का कितना भंडार हो गया हैं तथा तत्संबंधी खाद्यान्न-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) खाद्यान्नों के विद्यमान भंडार में से कितनी मात्रा को सार्वजानिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने की अनुमति दी गई हैं और कौन-कौन से खाद्यान्नों को कितनी-कितनी मात्रा में खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई हैं; और

(ग) सरकार के पास मौजूदा खाद्यान्नों के भारी मात्रा में भंडार और उसके समुचित रख-रखाव के अभाव में उसके सड़ जाने को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार जनता को उचित दर की दुकानों के माध्यम से सस्ती दरों पर गेहूं/चावल उपलब्ध कराएगी?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चालू रबी विपणन मौसम 1995-96 में 1.12.1995 तक 360 रूपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 123.18 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की जा चुकी हैं। इस

c स्टाक की कीमत (प्रासंगिक खर्चो सहित) 5517.05 करोड़ रूपए आकी गई हैं।

1.11.1995 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में सरकार के पास उपलब्ध गेहूं और चावल का स्टाक निम्नानुसार थाः

	(लाख मीटरी टन)
गेहूं	157.70
चावल	124.08
	281.78

(ख) सार्वजानिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल का आवंटन विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग, उनकी संगत जरूरतों, उठान प्रवृत्ति , केन्द्रीय पूल में स्टाक, मौसमी उपलब्धता आदि के आधार पर माह दर माह किया जाता हैं।

1995-96 के दौरान खुले बाजार में 55 लाख मीटरी टन गेहूं और 15 मीटरी टन चावल की बिक्री करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को प्राधिकृत किया जा चुका हैं। 1995-96 (अक्तूबर, 1995 तक) के दौरान सार्वजानिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेची गई गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार हैंः-

(लाख मीटरी टन)

	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	खुली बिक्री
गेहूं	26.89	20.47
चावल	53.90	10.70

(ग) प्रचालित केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सी.आई.पी.) पर भी गेहूं और चावल को जारी करने से सरकार पर सब्सिडी का भारी बोझ पड़ेगा। 1.2.1994 के बाद से खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्वि नहीं हुई हैं।

Commitments for Export of Foodgrains

2091. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:
SHRI RAM JETHMALANI:
SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI BHAGABAN MAJHI:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have made any foodgrains export commitment to China, South Karea, Bangladesh and some other countries as reported in the Hindustan Times of November 29, 1995;

(b) if so, the details of export orders received from each of these countries for the supply of foodgrains;

(c) the quantity and value of foodgrains exported from India during the year 1994-95 and so far in 1995-96;

(d) whether Government is facing any problems in meeting the export commitments and if so, the details thereof; and

(e) by when Government propose to meet its export commitments made to the foreign countries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Food Corporation of India has been permitted to export/sell for exports 2.5 million tonnes of non-durum wheat and 2.0 million tonnes of fine & superfine rice during 1995-96 (since raised to 3 million tonnes) from the public stocks. Non-durum wheat and fine and superfine rice is sold by FCI to private exporters and Central Public Sectors Undertakings under their Open Market Sale Scheme. The details of the contracts for export of rice are not maintained.

(c) The quantity and value of foodgrains exported during 1994-95 and